आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 07.09.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य सरकार, पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाला चारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में घण्टाघर के सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का लोकार्पण किया।
- हरिद्वार में होने वाले अर्द्धकुंभ 2027 के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया; श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए लगभग 54 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री ने जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की। कहा– ये परियोजनाएँ जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाएंगी।

साइलेज योजना विस्तार

राज्य में पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाला चारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पशु पोषण सुनिश्चित होगा, दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

देहरादून में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा की संयुक्त अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में साइलेज योजना के विस्तार पर सहमति बनी।

साइलेज योजना पहले से ही राज्य के दस पर्वतीय जिलों में संचालित है। अब इसे और व्यापक रूप देने का फैसला किया गया है ताकि अधिक पशुपालक लाभान्वित हो सकें। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि विभागों के तालमेल से किसानों और पशुपालकों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सहकारिता की भागीदारी से लागत में कमी आएगी और दुग्ध क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे।

बैठक में यह भी तय हुआ कि विभागीय समन्वय को संस्थागत रूप दिया जाएगा ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो और पशुपालकों को स्थायी लाभ मिल सके।

लोकार्पण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून के ऐतिहासिक घण्टाघर के सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाए गए 4 आधुनिक "हिलांस–कम–किचन आउटलेट्स" का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से नये स्वरूप में तैयार घण्टाघर अब न केवल शहर की शोभा बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून में चार स्थानों– कलेक्ट्रेट, कोरोनेशन अस्पताल, गुच्चुपानी और आईएसबीटी पर हिलांस कैंटीनों की शुरुआत भी की गई है, जो आम लोगों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण वस्तुएँ उपलब्ध कराएँगी और स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाएँगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए लगभग 14 सौ करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं और 11 स्थानों पर निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के डालनवाला थाने में स्थापित 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा संभावित राज्य है और ऐसे में समय रहते चेतावनी देना बेहद जरूरी है। ये सायरन आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 और 16 किलोमीटर की रेंज वाले ये सायरन प्राकृतिक आपदाओं के समय अलर्ट देंगे और नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी होंगे। समय पर चेतावनी मिलने से जानमाल की हानि कम होगी और राहत व बचाव कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली का नियमित परीक्षण किया जाए और जनता को इसके बारे में जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने डालनवाला थाने में बाल थाने का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों, उत्तराखंड पीसीएस एसोसिएशन और पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में सहायता राशि प्रदान की।

निरीक्षण

चम्पावत जिले के छमनिया, लोहाघाट में 256 करोड़ की लागत से बन रहे महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का खेल एवं युवा कल्याण सचिव अमित सिन्हा ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को समय पर और गुणवत्तापूर्वक काम पूरा करने के निर्देश दिए।

सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि यह प्रदेश का तीसरा बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज होगा, जो स्थानीय लोगों के साथ ही पूरे उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को देखते हुए लक्ष्य है कि यहां से पदक विजेता तैयार किए जाएं। पहले चरण में ग्राउंड, हॉस्टल और प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि जल्द कोचिंग शुरू हो सके। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर काम करने के निर्देश दिए और कहा कि एक से डेढ़ साल में कॉलेज तैयार हो जाएगा।

भिक्षावृत्ति रोकथाम

देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पहले चरण में 51 बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में दाखिला दिलाया गया और दूसरे चरण में 31 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। इस उद्देश्य से साधूराम इंटर कॉलेज में इंटेंसिव केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है।

अर्द्धकुंभ 2027– मास्टर प्लान

अर्द्धकुंभ 2027 के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बनी इस कार्ययोजना में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए लगभग 54 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाए रखने के लिये दो हजार 924 बेड की व्यवस्था होगी। इनमें 35 अस्थायी अस्पतालों में 373 बेड, 13 सरकारी अस्पतालों में एक हजार 101 बेड और प्राइवेट अस्पतालों में एक हजार 450 बेड आरक्षित किए जाएंगे। 40 एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी, जिनमें 24 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। श्रद्धालुओं के खानपान की सुरक्षा के लिए तीन नई फूड सेफ्टी वैन भी उपलब्ध होंगी।

हरिद्वार के रोशनाबाद में 120 लाख की लागत से ड्रग वायर हाउस बनाया जाएगा और चार नए वाहन खरीदे जाएंगे। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए फागिंग मशीनें खरीदी जाएंगी। वहीं, भूपतवाला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन की सुविधा बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2027 का अर्द्धकुंभ दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित होगा। सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी श्रद्धालु स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।

जनजाति कल्याण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएँ जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाएंगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 128 जनजातीय गांवों का चयन जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में किया गया है। कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य विद्यालय संचालित हैं। पिथौरागढ़ में भी एक नया एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तीन आईटीआई संस्थान संचालित हैं। जनजातीय बच्चों को छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएँ दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की परंपराओं और रीति–रिवाजों के संरक्षण के लिए उन्हें समान नागरिक संहिता से बाहर रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान में सौंदर्यीकरण, बालिकाओं के लिए हाईटेक शौचालय और आदि लक्ष्य संस्थान में डाइनिंग हॉल निर्माण की घोषणा भी की।

अतिवृष्टि / मौसम

उत्तरकाशी में यमुना घाटी स्थित नौगांव बाजार में कल शाम अतिवृष्टि से मलबा आने पर कई दुकानों और आवासीय भवनों को नुकसान हुआ। एक आवासीय भवन मलबे में दब गया और छह से अधिक भवनों में पानी भर गया। हालांकि इससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी से बातचीत कर राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कार्य में जुटी हैं और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और सभी लोग सुरक्षित हैं।

इधर, आज राज्य में कहीं–कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौस्म विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है।

पितृपक्ष

आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे पूर्वजों के प्रति आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है।

धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और दान से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उत्तराखंड में भी यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गंगा, यमुना और अलकनंदा तटों पर श्रद्धालु पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी को इस अवसर पर प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है।

ग्रामीण इलाकों में भी घर–घर विशेष भोजन तैयार कर पहले कौवों और गौ माता को अर्पित करने की परंपरा निभाई जाती है।